



Lakshya IAS

academy

15

Aug 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)

लक्ष्य IAS तेलीबाग लखनऊ

 Lakshya IAS Academy

 8182093320



1. संसद ने खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया

संसद ने गुरुवार, 13 अगस्त को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पष्ट मंजूरी मिल गई। इस कानून का मुख्य उद्देश्य खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्य सरकारों की शक्ति को सीमित करना है, ताकि पूरे देश में खनिजों की मानक दरें सुनिश्चित की जा सकें। केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज सहित प्रमुख खनिजों को नियंत्रित करेगी—जबकि राज्यों के पास 49 गौण (छोटे) खनिजों पर नियामक नियंत्रण बना रहेगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह अधिनियम संघ सूची की प्रविष्टि 54 पर आधारित है और राज्यों के खनिज राजस्व के हिस्से को सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे राज्य के खजानों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।



Parliament passes Mines and Minerals Amendment Bill, 2026

Parliament on Thursday 13 August passed the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026, after clear approval from both the Lok Sabha and Rajya Sabha. The key objective of this legislation is to restrict state governments' authority to impose taxes on mineral rights and mineral-bearing lands, ensuring standard nationwide mineral rates. Union Mines Minister G. Kishan Reddy clarified that the Centre will regulate major minerals, including coal, limestone, iron ore, copper, and manganese—while states retain regulatory control over 49 minor minerals. The Minister assured that the act relies on Entry 54 of the Union List and that state mineral revenue shares will remain protected, preventing potential losses to state treasuries.



मुख्य बिंदु:

- कर संबंधी प्रतिबंध: यह संशोधन भारत भर में समान दरें बनाने के लिए राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर अलग से कर लगाने से रोकता है।
- नियंत्रण का विभाजन: केंद्र सरकार मुख्य प्रमुख खनिजों (कोयला, लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर और मैंगनीज) को नियंत्रित करती है, जबकि राज्य सरकारें 49 गौण खनिजों पर नियंत्रण बनाए रखती हैं।
- संवैधानिक प्रावधान: यह कानून संघ सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 54 के तहत लागू किया गया था, जो संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है।

Key points:

- Taxing Restrictions: The Amendment restricts state governments from levying separate taxes on mineral rights and mineral-bearing lands to create uniform rates across India.
- Division of Control: The Central Government regulates key major minerals (coal, iron ore, copper, limestone, and manganese), while state governments maintain control over 49 minor minerals.
- Constitutional Provision: The legislation was enacted under Entry 54 of the Union List (Seventh Schedule), which grants Parliament power to regulate mines and mineral development in the public interest.



2. एआई फ्रेमवर्क ने छिपे हुए कैंसर स्टेम-सदृश

कोशिकाओं का लगाया पता

एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (SNBNCBS) और अशोका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2026 में 'एसीएससीएनडी' (ACSCeND) नाम से एक एआई-आधारित कम्प्यूटेशनल फ्रेमवर्क विकसित किया है। यह उपकरण ट्यूमर के दोबारा उभरने, मेटास्टेसिस (शरीर में कैंसर के फैलने) और उपचार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार दुर्लभ कैंसर स्टेम-सदृश कोशिका (सीएससी) आबादी का पता लगाता है। एसीएससीएनडी मानक बल्क आरएनए अनुक्रमण (सीक्वेंसिंग) डेटा का विश्लेषण करने के लिए उच्च-परिभाषा (हाई-रिज़ॉल्यूशन) सिंगल-सेल सीक्वेंसिंग को दीप लर्निंग एल्गोरिदम के साथ जोड़ता है। यह कैंसर स्टेम-सदृश कोशिकाओं को तीन विकासात्मक चरणों में वर्गीकृत करता है: प्लुरिपोटेंट-सदृश, मल्टिपोटेंट-सदृश और यूनिपोटेंट-सदृश। निष्कर्षों से पता चलता है कि प्लुरिपोटेंट-सदृश स्टेम कोशिकाओं के उच्च अनुपात वाले ट्यूमर का सीधा संबंध रोगियों के कम जीवित रहने की दर, पुनरावृत्ति (कैंसर के लौटने) के उच्च जोखिम और इम्यूनोथेरेपी के प्रति कम प्रभावशीलता से है। अपने पूर्व ऑनकोमार्क प्लेटफॉर्म के आधार पर बनाई गई यह नई खोज आक्रामक कैंसर में आणविक उत्तरजीविता (मॉलिक्यूलर सर्वाइवल) तंत्र की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।



AI Framework Detects Hidden Cancer Stem-Like Cells

Scientists from the S. N. Bose National Centre for Basic Sciences (SNBNCBS) and Ashoka University have developed an AI-based computational framework named ACSCeND in August 2026. The tool detects rare cancer stem-like cell (CSC) populations responsible for tumour recurrence, metastasis, and treatment resistance. ACSCeND combines high-resolution single-cell sequencing with deep learning algorithms to analyze standard bulk RNA sequencing data. It classifies cancer stem-like cells into three developmental stages: pluripotent-like, multipotent-like, and unipotent-like. Findings reveal that tumours with higher proportions of pluripotent-like stem cells correspond to poorer patient survival, higher relapse risks, and suppressed immunotherapy responses. Building upon their prior OncoMark platform, this innovation provides crucial insights into molecular survival mechanisms in aggressive cancers.



मुख्य बिंदु:

- डेवलपर और फ्रेमवर्क का नाम: SNBNCBS और अशोका यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित, एआई फ्रेमवर्क एसीएससीएनडी छिपी हुई कैंसर स्टेम-सदृश कोशिकाओं की पहचान करने के लिए दीप लर्निंग और बल्क आरएनए सीक्वेंसिंग का उपयोग करता है।
- तीन विकासात्मक स्थितियां: यह कैंसर स्टेम-सदृश कोशिकाओं को तीन अलग-अलग क्षमताओं की स्थितियों में वर्गीकृत करता है: प्लुरिपोटेंट-सदृश, मल्टिपोटेंट-सदृश और यूनिपोटेंट-सदृश।
- चिकित्सकीय प्रभाव: प्लुरिपोटेंट-सदृश स्टेम कोशिकाओं का उच्च सांद्रण (अधिक मात्रा) सीधे तौर पर कम समग्र उत्तरजीविता दर, ट्यूमर की बढ़ती पुनरावृत्ति और आधुनिक इम्यूनोथेरेपी के प्रति प्रतिरोध से संबंधित है।

Key points:

- Developer and Framework Name: Developed by SNBNCBS and Ashoka University, the AI framework ACSCeND leverages deep learning and bulk RNA sequencing to identify hidden cancer stem-like cells.
- Three Developmental States: It categorizes cancer stem-like cells into three distinct potency states: pluripotent-like, multipotent-like, and unipotent-like.
- Clinical Impact: Higher concentrations of pluripotent-like stem cells directly correlate with poorer overall survival, increased tumor recurrence, and resistance to modern immunotherapies.

3. भारतीय सेना ने सीआईएसएफ कर्मियों को दिया 3.

प्रशिक्षण

भारतीय सेना ने अगस्त 2026 में त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम (एमबीबी) हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों के लिए 14 दिवसीय विशेष संयुक्त सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स और रेड शील्ड डिवीजन के तहत आयोजित यह पहल क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सिविल-मिलिट्री फ्यूजन (नागरिक-सैन्य एकीकरण) रणनीति का एक हिस्सा है। प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण विमानन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सामरिक कौशल, त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) ड्रिल, पहुंच नियंत्रण, परिधि सुदृढ़ीकरण, काउंटर-ड्रोन संचालन और तीव्र आकस्मिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित एमबीबी हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख पारगमन केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रम अगरतला सैन्य स्टेशन पर संपन्न हुआ, जिसने सीआईएसएफ कर्मियों को आधुनिक खतरे से निपटने की तकनीकों से लैस किया।



Indian Army Trains CISF Personnel

The Indian Army conducted a 14-day specialized joint security training program for Central Industrial Security Force (CISF) personnel at Maharaja Bir Bikram (MBB) Airport in Agartala, Tripura in August 2026. Organized under the Indian Army's Spear Corps and Red Shield Division, the initiative forms part of a civil-military fusion strategy to enhance regional security. The training focused on tactical skills, Quick Reaction Team (QRT) drills, access control, perimeter hardening, counter-drone operations, and rapid contingency responses to protect critical aviation infrastructure. Located near the India-Bangladesh border, MBB Airport serves as a key transit hub in Northeast India. The program concluded at the Agartala Military Station, equipping CISF personnel with modern threat-mitigation techniques.



Key points:

- Joint Training Initiative: The Indian Army's Spear Corps and Red Shield Division conducted a 14-day specialized security program for CISF personnel at Maharaja Bir Bikram Airport, Agartala.
- Core Objectives: Focus areas included Quick Reaction Team (QRT) drills, tactical readiness, counter-drone mechanisms, perimeter hardening, and contingency handling to bolster aviation security.
- Civil-Military Fusion: The program reflects an effort to integrate military capabilities with paramilitary airport security forces in border regions.

मुख्य बिंदु:

- संयुक्त प्रशिक्षण पहल: भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स और रेड शील्ड डिवीजन ने महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे, अगरतला में सीआईएसएफ कर्मियों के लिए 14 दिवसीय विशेष सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया।
- मुख्य उद्देश्य: ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) ड्रिल, सामरिक तत्परता, काउंटर-ड्रोन तंत्र, परिधि सुदृढ़ीकरण और आकस्मिक स्थितियों से निपटना शामिल था।
- सिविल-मिलिट्री फ्यूजन: यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में अर्धसैनिक हवाई अड्डा सुरक्षा बलों के साथ सैन्य क्षमताओं को एकीकृत करने के प्रयास को दर्शाता है।

4. गज गौरव पुरस्कार 2026

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व हाथी दिवस समारोह के दौरान 13 अगस्त को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। इन राष्ट्रीय सम्मानों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल) के सात महावत शामिल हैं, जिन्हें भीषण बाढ़ के दौरान बचाव कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ₹30 जाइंट स्टेप्स नामक दस्तावेज़ जारी किया, जिसमें 2020 से 2026 तक प्रोजेक्ट एलीफेंट की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत (कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) में मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपये की क्षेत्रीय कार्य योजना शुरू की गई। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य की एआई-संचालित 'हनुमान' (H.A.N.U.M.A.N.) वन्यजीव निगरानी पहल पर भी प्रकाश डाला।



4. Gaj Gaurav Awards 2026

The Gaj Gaurav Awards 2026 were conferred in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, on 13 August, during the World Elephant Day celebrations organized by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The national honors recognized frontline workers, including seven mahouts from Jaldapara National Park (West Bengal) honored for rescue work during severe floods. During the event, Union Minister of State Kirti Vardhan Singh released the document "30 Giant Steps", outlining Project Elephant's achievements from 2020 to 2026. Additionally, a Rs 500 crore Regional Action Plan was introduced to address Human-Elephant Conflict in Southern India (Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu). Andhra Pradesh's Deputy Chief Minister Pawan Kalyan also highlighted the state's AI-driven H.A.N.U.M.A.N. wildlife monitoring initiative.



मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय पुरस्कार मान्यता: गज गौरव पुरस्कार 2026 ने फ्रंटलाइन संरक्षण प्रयासों को सम्मानित किया, जिसमें भीषण बाढ़ के दौरान बंधक हाथियों और जंगली गैंडों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान के सात महावतों को सम्मानित करना शामिल है।
- 500 करोड़ रुपये की संघर्ष प्रबंधन योजना: कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मानव-हाथी संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन द्वारा समर्थित एक क्षेत्रीय कार्य योजना शुरू की गई।
- नीतिगत और तकनीकी पहल: मंत्रालय ने प्रोजेक्ट एलीफेंट की उपलब्धियों (2020-2026) पर प्रकाश डालते हुए ₹30 जाइंट स्टेप्स रिपोर्ट जारी की, साथ ही आंध्र प्रदेश की तकनीक-संचालित 'हनुमान' (H.A.N.U.M.A.N.) वन्यजीव निगरानी प्रणाली की भी शुरुआत की गई।

Key points:

- National Awards Recognition: The Gaj Gaurav Awards 2026 honored frontline conservation efforts, including seven mahouts from West Bengal's Jaldapara National Park for saving captive elephants and wild rhinos during severe floods.
- Rs 500 Crore Conflict Management Plan: A Regional Action Plan supported by a Rs 500 crore allocation was launched to manage Human-Elephant Conflict across Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu.
- Policy and Tech Initiatives: The Ministry released the "30 Giant Steps" report highlighting Project Elephant achievements (2020-2026), alongside Andhra Pradesh's tech-driven H.A.N.U.M.A.N. wildlife monitoring system.

5. तमिलनाडु ने 97 MoU पर हस्ताक्षर किए

तमिलनाडु ने गुरुवार 13 अगस्त को चेन्नई में 'वेत्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 2026' में 67,452 करोड़ रुपये के 97 नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते 20 जिलों में ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा, लाइफ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) जैसे क्षेत्रों में नए और मौजूदा (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड) प्रोजेक्ट्स से संबंधित हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन सहित 15 से अधिक देशों की कंपनियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें विदेशी निवेश का योगदान 15,050 करोड़ रुपये रहा। इन पहलों से 1.07 लाख से 1.20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, प्रशासन के नए कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर 104 एमओयू के जरिए राज्य का कुल आकर्षित निवेश 1,02,514 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 2035 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के तमिलनाडु के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।



मुख्य बिंदु:

- निवेश का पैमाना और रोजगार: तमिलनाडु ने 67,452 करोड़ रुपये मूल्य के 97 एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे 20 जिलों में 1.07 लाख से 1.20 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन का अनुमान है।
- वैश्विक भागीदारी: 15 से अधिक देशों की कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश समझौतों का योगदान 15,050 करोड़ रुपये (लगभग 1.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा।
- आर्थिक दृष्टिकोण: इन निवेशों ने 100 दिनों के भीतर राज्य की कुल निवेश प्रतिबद्धताओं को 1.02 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया है, जो 2035 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के तमिलनाडु के लक्ष्य का समर्थन करता है।

5. Tamil Nadu Signs 97 MoUs

Tamil Nadu, on Thursday 13th August, signed 97 fresh Memoranda of Understanding (MoUs) worth Rs 67,452 crore at the Vetti Tamil Nadu Investors Conclave 2026 in Chennai. The agreements cover greenfield and brownfield projects spanning automotive, renewable energy, life sciences, electronics, data centers, and R and D across 20 districts. Companies from over 15 countries, including the US, Germany, Japan, South Korea, and the UK, participated, with foreign investments contributing Rs 15,050 crore. These initiatives are expected to generate between 1.07 lakh and 1.20 lakh jobs. With this, the state's total attracted investment reached Rs 1,02,514 crore via 104 MoUs within 100 days of the new administration, advancing Tamil Nadu's long-term economic target of becoming a USD 1.5 trillion economy by 2035.



Key points:

- Investment Scale and Employment: Tamil Nadu signed 97 MoUs valued at Rs 67,452 crore, projecting the creation of over 1.07 lakh to 1.20 lakh jobs across 20 districts.
- Global Participation: Firms from more than 15 nations participated, with overseas investment pacts contributing Rs 15,050 crore (~ USD 1.58 billion) across sectors like electronics, renewables, and data centers.
- Economic Vision: The investments push total state commitments past Rs 1.02 lakh crore within 100 days, supporting Tamil Nadu's goal to achieve a USD 1.5 trillion economy by 2035.

6. राष्ट्रपति मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए

❖ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप (अकादमी रत्न) और पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) प्रदान किए। इन पुरस्कारों ने संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, जनजातीय कला, कठपुतली और पारंपरिक कला रूपों सहित प्रदर्शन कलाओं में असाधारण योगदान को मान्यता दी। सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की विविध कलात्मक विरासत को रेखांकित किया और विलुप्त होने की कगार पर खड़ी पारंपरिक लोक कला शैलियों के दस्तावेजीकरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कला-दीक्षा प्रशिक्षण पहल आयोजित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी की सराहना की और दिग्गज कलाकारों से भावी पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रदान करने का आह्वान किया।



मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय मान्यता: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न प्रदर्शन कला विधाओं के 100 से अधिक विशिष्ट कलाकारों को 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए।
- संरक्षण पर ध्यान: राष्ट्रपति ने विलुप्त होने के जोखिम का सामना कर रही संकटग्रस्त लोक कला शैलियों को सहेजने और उनके दस्तावेजीकरण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
- युवा मार्गदर्शन: अकादमी के 'कला-दीक्षा' कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए दिग्गज कलाकारों से कलाकारों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित और तराशने का आह्वान किया।

6. President Murmu confers Sangeet Natak Akademi

Akademi Fellowships and Awards

❖ President Droupadi Murmu conferred the prestigious Sangeet Natak Akademi Fellowships (Akademi Ratna) and Awards (Akademi Puraskar) for 2024 and 2025 to over 100 artists at a ceremony in New Delhi on 13 August. The awards recognized exceptional contributions across performing arts, including music, dance, theatre, folk, tribal arts, puppetry, and traditional art forms. Addressing the gathering, President Murmu highlighted India's diverse artistic heritage and stressed the urgent need to document traditional folk art forms facing extinction. She commended the Sangeet Natak Akademi for organizing the Kala-Diksha training initiative and urged veteran artists to mentor future generations.



Key points:

- National Recognition: President Droupadi Murmu presented Sangeet Natak Akademi Fellowships and Awards for 2024-2025 to over 100 distinguished artists across various performing art disciplines.
- Preservation Focus: The President emphasized the urgent need to document and preserve vulnerable folk art forms facing extinction.
- Youth Mentorship: Highlighted the Akademi's Kala-Diksha program, calling upon veteran artists to train and groom the next generation of performers.

7. एस्टन विला पर 2-1 की जीत के साथ पीएसजी ने

यूईएफए सुपर कप का खिताब बरकरार रखा

✎ पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने 12

अगस्त को खेले गए एक कड़े मुकाबले में एस्टन विला को 2-1 से हराकर यूईएफए सुपर कप का खिताब सफलतापूर्वक अपने पास बरकरार



रखा। पीएसजी ने 20वें मिनट में खविचा क्वारत्सखेलिया के शानदार गोल की बदौलत शुरुआती बढ़त बना ली। हालांकि, एस्टन विला के 17 वर्षीय पदार्पण खिलाड़ी (डेब्यूटन) ब्रायन मैजो ने हाफ-टाइम से ठीक पहले गोल करके बराबरी हासिल की और यूईएफए सुपर कप में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद, पीएसजी ने 61वें मिनट में तब फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया जब डेजायर डोए ने निर्णायक विजयी गोल किया, जिसकी पुष्टि वीएआर (VAR) जांच द्वारा की गई। यह जीत पीएसजी की लगातार दूसरी सुपर कप जीत है, जिसके साथ ही वह एसी मिलान और रियल मैड्रिड के बाद इस ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखने वाली केवल तीसरी विशिष्ट टीम बन गई है। इस परिणाम के साथ, पीएसजी के प्रबंधक लुईस एनरिक ने 2023 के बाद से अपनी 13वीं ट्रॉफी हासिल की, जबकि उनाई एमेरी की विला टीम पीछे रह गई।

मुख्य बिंदु:

- लगातार दो बार के चैंपियन: पीएसजी ने यूईएफए सुपर कप का खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा, जिससे वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले केवल एसी मिलान और रियल मैड्रिड जैसे क्लबों की सूची में शामिल हो गया।
- निर्णायक गोलकर्ता: खविचा क्वारत्सखेलिया ने गोल की शुरुआत की, और डेजायर डोए ने 61वें मिनट में विजयी गोल करके 2-1 की जीत सुनिश्चित की।
- रिकॉर्ड प्रदर्शन: एस्टन विला के ब्रायन मैजो ने पहले हाफ में बराबरी का गोल दागकर यूईएफए सुपर कप मैच में सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया।

7. PSG retain UEFA Super Cup with 2-1 win over Aston Villa

✎ Paris Saint-Germain (PSG)

successfully retained the UEFA Super Cup by defeating Aston Villa 2-1 in a



closely contested match on August 12. PSG took an early lead in the 20th minute through a brilliant strike by Khvicha Kvaratskhelia. Although Aston Villa's 17-year-old debutant Brian Madjo equalized just before halftime, becoming the youngest-ever UEFA Super Cup scorer, PSG regained control in the 61st minute when Desire Doue scored the decisive winner, confirmed by a VAR check. This victory marks PSG's second consecutive Super Cup win, joining an elite group alongside AC Milan and Real Madrid as the only teams to retain the trophy. With this result, PSG manager Luis Enrique secured his 13th trophy since 2023, while Unai Emery's Villa side fell short.

Key points:

- Back-to-Back Champions: PSG successfully retained the UEFA Super Cup, joining AC Milan and Real Madrid as the only clubs to accomplish this feat.
- Decisive Scorers: Khvicha Kvaratskhelia opened the scoring, and Desire Doue netted the winner in the 61st minute to secure the 2-1 victory.
- Record Performance: Aston Villa's Brian Madjo made history as the youngest-ever goalscorer in a UEFA Super Cup match with his first-half equalizer.

8. लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बीसोलो न्यांती नई

दिल्ली पहुंचीं

लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बीसोलो न्यांती भारत और लाइबेरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 13 अगस्त को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचीं। उन्होंने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम तय किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, लाइबेरिया भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना का लाभ उठाता है, जो भारत में इमारती लकड़ी, रबर और वनस्पति तेल जैसे लाइबेरियाई निर्यात को सुगम बनाती है। लाइबेरिया में खनन, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित प्रमुख क्षेत्रों में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, लाइबेरिया भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का एक सक्रिय सदस्य है, जो व्यापार और आर्थिक साझेदारी के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।



Liberia's Foreign Minister Sara Beysolow Nyanti arrives in New Delhi

Liberia's Minister of Foreign Affairs, Sara Beysolow Nyanti, arrived in New Delhi on a two-day official visit, on August 13, to bolster bilateral relations between India and Liberia. She scheduled bilateral talks with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar at Hyderabad House. According to the Ministry of External Affairs (MEA), Liberia benefits from India's Duty-Free Tariff Preference (DFTP) scheme, facilitating Liberian exports such as timber, rubber, and vegetable oil to India. Over 200 Indian firms operate in Liberia across key sectors including mining, pharmaceuticals, health care, and electronics. Additionally, Liberia is an active member of the India-led International Solar Alliance (ISA), reflecting growing cooperation in renewable energy alongside trade and economic partnerships.



मुख्य बिंदु:

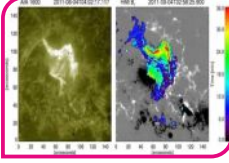
- उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता: विदेश मंत्री सारा बीसोलो न्यांती ने भारत-लाइबेरिया संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने हेतु नई दिल्ली का दौरा किया।
- व्यापार और निवेश संबंध: लाइबेरिया भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना का लाभ उठाता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, खनन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में 200 से अधिक भारतीय व्यवसाय कार्यरत हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी: लाइबेरिया भारत द्वारा प्रचारित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का सदस्य है, जो बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाता है।

Key points:

- High-Level Bilateral Talks: Foreign Minister Sara Beysolow Nyanti visited New Delhi to hold bilateral discussions with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to strengthen India-Liberia ties.
- Trade and Investment Links: Liberia benefits from India's Duty-Free Tariff Preference (DFTP) scheme, with over 200 Indian businesses operating in sectors like pharmaceuticals, mining, and electronics.
- Renewable Energy Partnership: Liberia is a member of the India-promoted International Solar Alliance (ISA), furthering multilateral cooperation.

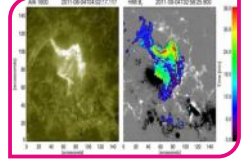
9. नया कंप्यूटर मॉडल सौर तूफानों के पूर्वानुमान में मदद के लिए चुंबकीय ऊर्जा के निर्माण का पता लगाता है

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने, अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के सहयोग से, अगस्त 2026 में सूर्य पर चुंबकीय ऊर्जा के निर्माण का पता लगाने के लिए एक 3D मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक (MHD) कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल सौर वायुमंडल में घुमावदार चुंबकीय प्रवाह रस्सियों (MFRs) के बनने और उनके विस्फोट का अनुकरण (सिमुलेशन) करता है, जो कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) को ट्रिगर करते हैं। नासा के उपकरणों से प्राप्त अवलोकन संबंधी आंकड़ों के साथ सिमुलेशन का सत्यापन करके, शोधकर्ताओं ने यह स्थापित किया कि चुंबकीय पुनर्संयोजन की दर सीधे तौर पर सीएमई (CME) के त्वरण (एक्सेलरेशन) से संबंधित है। आईआईए की 'नोवा' सुपरकंप्यूटिंग सुविधा पर निष्पादित, यह ढांचा अंतरिक्ष-मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर बनाता है, जिससे पृथ्वी के पावर ग्रिड, उपग्रहों और संचार प्रणालियों पर सौर तूफानों की आगमन गति, प्रक्षेपवक्र (ट्रैजेक्टरी) और सम्भावित प्रभाव की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है।



9. New computer model tracks magnetic energy build-up to help forecast solar storms

Scientists led by the Indian Institute of Astrophysics (IIA), in collaboration with international researchers, have developed a 3D magnetohydrodynamic (MHD) computer simulation model to track magnetic energy build-up on the Sun in August 2026. The model simulates the formation and eruption of twisted magnetic flux ropes (MFRs) in the solar atmosphere, which trigger Coronal Mass Ejections (CMEs). By validating the simulations against observational data from NASA's instruments, researchers established that the rate of magnetic reconnection directly correlates with CME acceleration. Executed on IIA's NOVA supercomputing facility, this framework enhances space-weather forecasting, aiding in predicting the arrival speed, trajectory, and potential impact of solar storms on Earth's power grids, satellites, and communications.



मुख्य बिंदु:

- प्रमुख अनुसंधान संस्थान: यह अध्ययन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के नेतृत्व में किया गया था।
- कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) का पूर्वानुमान: 3D मॉडल यह समझने के लिए घुमावदार चुंबकीय प्रवाह रस्सियों (MFRs) का पता लगाता है कि चुंबकीय ऊर्जा कैसे बनती है और शक्तिशाली सौर विस्फोटों को ट्रिगर करती है।
- पुनर्संयोजन और त्वरण का सीधा संबंध: शोध ने साबित किया कि चुंबकीय पुनर्संयोजन की दर सीधे तौर पर पृथ्वी की ओर सीएमई (CME) की गति और त्वरण को निर्धारित करती है।

Key points:

- Lead Research Institution: The study was led by the Indian Institute of Astrophysics (IIA), an autonomous institute under India's Department of Science and Technology (DST).
- Predicting Coronal Mass Ejections (CMEs): The 3D model tracks twisted magnetic flux ropes (MFRs) to understand how magnetic energy builds up and triggers powerful solar eruptions.
- Direct Reconnection-Acceleration Link: The research proved that the rate of magnetic reconnection directly determines the speed and acceleration of CMEs toward Earth.



10. गोवा में शुरू हुई 8 वीं ब्रिक्स महासागरीय-ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी बैठक

भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 12 अगस्त को गोवा में महासागर और ध्रुवीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (ओपीएसटी) पर ब्रिक्स कार्य समूह की 8वीं बैठक शुरू हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम आठ सदस्य देशों—ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों को एक साथ लाता है। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण, ध्रुवीय अनुसंधान बुनियादी ढांचे को साझा करने और महासागरीय अन्वेषण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव डॉ. एम. राजीवन ने भारत की ब्लू इकोनॉमी पहल पर मुख्य भाषण दिया, जिसमें टिकाऊ समुद्री विज्ञान के लिए बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया।



मुख्य बिंदु:

- मेजबान और स्थान: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित।
- मुख्य उद्देश्य: बहुपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान बुनियादी ढांचे के साझा उपयोग को बढ़ावा देना।
- कार्य समूह की पृष्ठभूमि: 2018 में स्थापित, ब्रिक्स ओपीएसटी कार्य समूह का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच समुद्री और ध्रुवीय विज्ञान में नवाचार, स्थिरता और सहयोगात्मक अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।

10. 8th BRICS Oceanic-Polar Science and Tech Meet Begins in Goa

The 8th Meeting of the BRICS Working Group on Ocean and Polar Science and Technology (OPST) commenced in Goa under India's 2026 BRICS Presidency on August 12. Hosted by the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) under the Ministry of Earth Sciences (MoES), the three-day event brings together scientists and officials from eight member nations—Brazil, China, Egypt, Indonesia, Russia, South Africa, the UAE, and India. The summit focuses on enhancing joint research, capacity building, sharing polar research infrastructure, and advancing ocean exploration. Former MoES Secretary Dr. M. Rajeevan delivered the keynote address on "India's Blue Economy Initiatives," emphasizing multilateral collaboration for sustainable marine science.



Key points:

- Host and Location: Hosted by the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) in Goa as part of India's BRICS Presidency.
- Core Objective: Fostering multilateral scientific cooperation, joint research projects, and shared utilization of polar and ocean research infrastructure.
- Working Group Background: Established in 2018, the BRICS OPST Working Group aims to drive innovation, sustainability, and collaborative research in marine and polar sciences across member states.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. अगस्त 2026 में 8वीं BRICS OPST बैठक की मेज़बानी करने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

- (a) कोच्चि, केरल (b) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
(c) वास्को डी गामा, गोवा (d) चेन्नई, तमिलनाडु

Q2. अगस्त 2026 में 3D मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक (MHD) सिमुलेशन मॉडल विकसित करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

- (a) हैदराबाद, तेलंगाना (b) बेंगलुरु, कर्नाटक
(c) पुणे, महाराष्ट्र (d) देहरादून, उत्तराखंड

Q3. लाइबेरिया की राजधानी क्या है, जिसकी विदेश मंत्री ने अगस्त 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा की थी?

- (a) फ्रीटाउन (b) यामौसौकरो
(c) अकरा (d) मोनरोविया

Q4. 2026 UEFA सुपर कप का खिताब बरकरार रखने के लिए पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) ने किस क्लब को पराजित किया?

- (a) एस्टन विला (b) टोटनहम हॉटस्पर
(c) एसी मिलान (d) रियल मैड्रिड

Q5. संगीत नाटक अकादमी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती है?

- (a) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(b) संस्कृति मंत्रालय
(c) शिक्षा मंत्रालय
(d) युवा मामले और खेल मंत्रालय

Q6. तमिलनाडु ने स्वयं को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है?

- (a) 2035 (b) 2038
(c) 2040 (d) 2045

Q1. Where is the headquarters of the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR), which hosted the 8th BRICS OPST Meeting in August 2026?

- (a) Kochi, Kerala
(b) Visakhapatnam, Andhra Pradesh
(c) Vasco da Gama, Goa
(d) Chennai, Tamil Nadu

Q2. Where is the headquarters of the Indian Institute of Astrophysics (IIA), which developed a 3D Magnetohydrodynamic (MHD) simulation model in August 2026?

- (a) Hyderabad, Telangana
(b) Bengaluru, Karnataka
(c) Pune, Maharashtra
(d) Dehradun, Uttarakhand

Q3. What is the capital of Liberia, whose Foreign Minister visited India on an official visit in August 2026?

- (a) Freetown (b) Yamoussoukro
(c) Accra (d) Monrovia

Q4. Which club did Paris Saint-Germain (PSG) defeat to retain the 2026 UEFA Super Cup title?

- (a) Aston Villa (b) Tottenham Hotspur
(c) AC Milan (d) Real Madrid

Q5. The Sangeet Natak Akademi functions as an autonomous body under which Union Ministry?

- (a) Ministry of Information and Broadcasting
(b) Ministry of Culture
(c) Ministry of Education
(d) Ministry of Youth Affairs and Sports

Q6. By which year has Tamil Nadu set the target of transforming itself into a US\$1.5 trillion economy?

- (a) 2035 (b) 2038
(c) 2040 (d) 2045



Q7. 13 अगस्त 2026 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर 'गज गौरव पुरस्कार 2026' किस शहर में प्रदान किए गए?

- (a) मैसूर, कर्नाटक
- (b) गुवाहाटी, असम
- (c) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
- (d) वायनाड, केरल

Q8. महाराजा बीर बिक्रम (MBB) हवाई अड्डा, जहाँ अगस्त 2026 में भारतीय सेना ने CISF कर्मियों के लिए संयुक्त सामरिक सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया, किस राज्य में स्थित है?

- (a) असम
- (b) मणिपुर
- (c) मेघालय
- (d) त्रिपुरा

Q9. SNBNCBS और अशोका विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 'ACSCeND' AI फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (a) रेटिनल स्कैन से शुरुआती डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाना
- (b) ट्यूमर के दोबारा होने और उपचार प्रतिरोध में योगदान देने वाली दुर्लभ कैन्सर स्टेम-जैसी कोशिकाओं की पहचान करना
- (c) सैटेलाइट इमेजिंग से भूमिगत खनिज भंडार का पता लगाना
- (d) जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में जैव-विविधता के संरचनात्मक बदलावों का अनुमान लगाना

Q10. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने के समय भारत के केंद्रीय खान मंत्री कौन थे?

- (a) सुया शिवकुमार
- (b) धर्मेन्द्र प्रधान
- (c) जी. किशन रेड्डी
- (d) ज्योतिरादित्य सिंधिया

Q7. On 13 August 2026, on the occasion of World Elephant Day, the 'Gaj Gaurav Awards 2026' were presented in which city?

- (a) Mysuru, Karnataka
- (b) Guwahati, Assam
- (c) Visakhapatnam, Andhra Pradesh
- (d) Wayanad, Kerala

Q8. The Maharaja Bir Bikram (MBB) Airport, where the Indian Army conducted joint tactical security training for CISF personnel in August 2026, is located in which state?

- (a) Assam
- (b) Manipur
- (c) Meghalaya
- (d) Tripura

Q9. What is the primary purpose of the 'ACSCeND' AI framework developed by scientists from SNBNCBS and Ashoka University?

- (a) To detect early-stage diabetic retinopathy using retinal scans
- (b) To identify rare cancer stem-like cells contributing to tumour recurrence and treatment resistance
- (c) To detect underground mineral deposits using satellite imaging
- (d) To predict structural changes in forest biodiversity caused by climate change

Q10. Who was the Union Minister of Mines when the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 was passed?

- (a) Suya Shivakumar
- (b) Dharmendra Pradhan
- (c) G. Kishan Reddy
- (d) Jyotiraditya Scindia

उत्तरमाला (Answer Key)

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | C | 2 | B | 3 | D | 4 | A | 5 | B | 6 | A | 7 | C | 8 | D | 9 | B | 10 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

